



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 104 राँची, सोमवार, 23 माघ, 1939 (श०)
12 फरवरी, 2018 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

19 जनवरी, 2018

विषय:-देवघर नगर निगम में कुल 40,14,34,500/-रु० (चालीस करोड़ चौदह लाख चौतीस हजार पाँच सौ रुपये) की लागत पर अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-5/यो०/ISBT/ देवघर/02/2017/न०वि०आ-394-- 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है ।

2. उक्त क्रम में शहरी क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है । इसी क्रम में देवघर नगर निगम के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल विकसित करने का निर्णय लिया गया है ।

उल्लेखनीय है कि श्रावणी मेला, 2018 के पूर्व प्रस्तावित अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल में आवश्यक आधारभूत संरचनाएँ यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र निर्मित किए जाने का प्रयास किया जाना है।

अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल निर्माण किये जाने के उपरान्त अन्य राज्यों से आने वाली बड़ी बसे कोर शहरी क्षेत्र से बाहर स्थित अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल में ठहरेंगी, जिससे शहरी क्षेत्र में बड़ी बसों के कारण उत्पन्न होने वाले जाम एवं अन्य ट्रैफिक समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही, इन डीजल इंजन वाले वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुआँ से शहरी क्षेत्र के आमजन को निजात मिलेगा। इन बड़े वाहनों के कारण शहरी क्षेत्र के सड़कों को भी होने वाले नुकसान से मुक्ति मिलेगी।

3. उक्त अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल हेतु देवघर नगर निगम के शहरी क्षेत्र से लगभग 4.5 कि०मी० की दूरी पर देवघर सुलतानगंज रोड (SH-22) के नजदीक बाघमारा ग्राम में उपलब्ध 20 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की गई है। बस टर्मिनल से रेलवे स्टेशन जाने हेतु अतिरिक्त 0.44 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

4. उक्त बस टर्मिनल का क्षेत्रफल (कार पार्किंग सहित) कुल 41.400 वर्ग मीटर होगा एवं इसमें लिफ्ट, सी०सी०टी०वी० आदि अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देवघर नगर निगम में प्रस्तावित बस टर्मिनल का निर्माण वर्ष 2045 की जनसंख्या को लक्षित कर किया जा रहा है, जिसमें एक साथ कुल 109 (एक सौ नौ) बसें खड़ी की जा सकती हैं।

5. परामर्शी IDFC द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) पर मुख्य अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की गई है:-

S.No.	DESCRIPTION	ESTIMATE (Rs.)
1	TERMINAL BUILDING	142960752
2	EXTERNAL DEVELOPMENT	58903566
3	ELECTRICAL WORK	45129540
4	FIRE FIGHTING WORKS	6108085
5	PLUMBING WORKS	2851348
6	EXTERNAL WORKS	32765107
7	CCTV WORKS	3040549
8	PARKING MANAGEMENT WORKS	14546600
9	WORKSHOP BUILDING INCLUDING PLUMBING	16710916
10	HAVC WORKS	2030000
11	LIFTS & ESCALATORS	22485162
12	PUBLIC CONVINCES BLOCK- PHASE-1	2698526
13	PLUMBING FOR PUBLIC CONVIENCES	381924
14	CARAGE OF MATERIAL	12082186
15	SINAGE WORK	3400000
16	ENVIRONMENTAL & SOCIAL IMPACT ASSESSMENT PLAN	2048000
SUB TOTAL		368142261
labour cess@ 1%		3681423
Consultant fee 1.25+1.25=2.50%		9203556
Juidco fee as centage		20407113
Total:-		401434353
Rounded to		401434500

6. योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत स्थापित सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (सर्वश्री जुडको लि०) के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से ससमय सुनिश्चित कराया जाएगा ।
7. उक्त योजना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा वहनीय व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना मद के अन्तर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से किये जाने का प्रस्ताव है:-
8. मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-(191/789) के अन्तर्गत उपशीर्ष-79- वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित प्रक्षेत्र (OSP/SCSP) से की जायेगी ।
9. स्वीकृत राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन, कोषागार से की जाएगी जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे । निकासी की गई राशि को सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (सर्वश्री जुडको लि०) के द्वारा पी०एल० खाते में संधारित करते हुए नियमानुसार व्यय किया जाएगा ।
10. उपर्युक्त क्रम में सर्वश्री जुडको लि० को योजना-सह-वित्त विभाग(वित्त प्रभाग) के संकल्प संख्या 3201 वि० दिनांक 4 नवम्बर, 2016 के आलोक में अनुमान्य Centage का भुगतान किया जाएगा ।
11. दिनांक 9 जनवरी, 2018 को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं०-09 के रूप में उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।
